

डिजिटल इंडिया

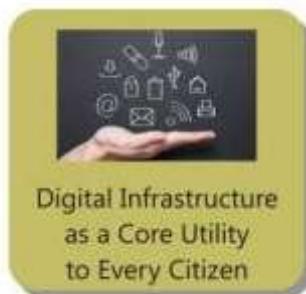
The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.



डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह के शुभारंभ पर, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई थी। डिजिटल और वित्तीय समावेशन जैसे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत में गांवों को ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने की परिकल्पना की गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को आम लोगों के घर तक पहुँचाया जा सके। यह कार्यक्रम देश भर में कार्यरत कॉमन सर्विस सेन्टर को सक्षम बनाकर लोगों तक इसकी पहुँच को सुलभ बनाता है।

कॉमन सर्विस सेन्टर योजना

कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की एक रणनीतिक आधारशिला हैं। ये भारत में गांवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को पहुँचाने की कड़ी हैं, जिससे डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान मिलता है।



Digital Infrastructure as a Core Utility to Every Citizen



Governance and Services on Demand



Digital Empowerment of Citizens

ग्रामीण भारत में सीएससी का महत्व सर्विस डिलीवरी प्लांट से कहीं अधिक हैं। वे परिवर्तन कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण क्षमता और आजीविका का निर्माण करते हैं। वे ग्रामीण नागरिकों को विशेष सहयोग देने के साथ बॉटम—अप ट्रृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं।

CSCs भारत के नागरिकों को G2C एवं B2C और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए फ्रंट—एंड डिलीवरी पॉइंट हैं। CSCs को ग्रामीण स्तर के उद्यमी (VLE) द्वारा संचालित किया जाता है, जो इन सेवाओं को देने के लिए नियुक्त एक स्थानीय व्यक्ति है और डिजिटल इंडिया के वास्तविक अम्बेसडर हैं। वे अपने लिए व्यवसाय उत्पन्न करते हैं और अपने समुदाय की सेवा भी करते हैं। इसलिए, और ग्रामीण आबादी के घर तक सभी सेवाओं को पहुँचाने के लिए सेवा वितरण के लिए एक बेहतर मंच विकसित किया गया है।

वर्तमान में सीएससी बहुत ही सारी आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं:

- ✓ वित्तीय समावेशन सेवाएँ: बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएँ।
- ✓ शिक्षा सेवाएँ: डिजिटल साक्षरता, पीएमजीदिशा, वित्तीय साक्षरता आदि।
- ✓ स्वास्थ्य सेवाएँ: टेलीमेडिसिन
- ✓ सरकार की नागरिक सेवाएँ: रेलवे टिकट, EPIC कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, पासपोर्ट, बिजली बिल संग्रह आदि
- ✓ व्यवसाय से संबंधित नागरिक सेवाएँ: डीटीएच सेवाएँ, मोबाइल रिचार्ज आदि।

सीएससी एसपीवी इन सेवाओं को पूरे देश में एक यूनिवर्सल तकनीकी प्लेटफार्म के माध्यम से पहुँचाता है, जिससे ई—सेवाएँ कहीं भी सुलभ हो जाती हैं। सीएससी ग्रामीण भारत में सर्विस डिलीवरी प्लांट से बढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है। वे परिवर्तन एजेंट के रूप में तैनात हैं, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण क्षमता और आजीविका का निर्माण करते हैं। वे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई के साथ कार्य करते हैं। सीएससी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा समान रूप से ग्रामीण भारत में सेवा वितरण के लिए सबसे आसान एवं सुलभ विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जिससे डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान हो रहा है।